

प्रदेश सरकार जल्द लाने जा रही है यूटिलिटी शिपिंग नीति

बड़े प्रोजेक्ट के लिए खाली हानि निलगाना आसान

तैयारी

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट व औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन आसानी से खाली मिल सकेगी। प्रदेश सरकार जल्द यूटिलिटी शिपिंग नीति-2021 लाएगी। इसके जरिए जमीन पर आबादी व परिसम्पत्तियां आसानी व बिना विवाद के अन्यत्र स्थानांतरित की जा सकेंगी। इससे मेंगा परियोजनाओं के लिए उक्त जमीन पर निर्माण कार्य कराना आसान हो जाएगा।

इस नीति का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक टाउनशिप, वेयरहाउस, उद्योग लगाने वाली परियोजना के लिए होगा। खास तौर पर गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजना के लिए निर्माण कार्य समय से शुरू हो सकेगा। इस समय एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीदने का काम चल रहा है। इसके अलावा जेवर



- औद्योगिक टाउनशिप, वेयरहाउस, उद्योग लगाने वाली परियोजनाओं को होगा फायदा
- गंगा एक्सप्रेस वे, जेवर एयरपोर्ट जैसे मेंगा प्रोजेक्ट का काम तेज हो सकेगा।

वर्तमान में इस तरह की कोई नीति नहीं है

अभी संबंधित विभागों में समन्वय के अभाव में देरी होती है। प्रस्तावित नीति में तय समय में इन परिसम्पत्तियों को हटाने व जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में इस तरह की कोई नीति नहीं है। केवल प्रशासकीय आदेशों पर परिसंपत्तियों का स्थानांतरण होता है। हाल हीं में औद्योगिक विकास विभाग ने इस नीति पर एक प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा था। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ सुझाव देकर बेहतर व उपयोगी बनाने का निर्देश दिया है।

एयरपोर्ट के लिए जमीन ले ली गई है। यहां यूटिलिटी शिपिंग का काम तेज हो सकेगा। असल में प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलने के बाद वहां बसी आबादी को हटाना आसान नहीं होता। अचल

परिसंपत्ति बिजली ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें, पोल, पंचायत भवन व स्कूल को अन्यत्र शिफ्ट करना विभिन्न कारणों से खासा मुश्किल होता है। इसके लिए नीति में व्यवस्था होगी।